

मजदूरों का अफ्ना कोई देश नहीं होता।

दुनिया के मजदूरों, एक हो!

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है।

नई सीरीज नम्बर 49

जुलाई 1992

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

50 पृष्ठे

पुलिस फायरिंग

भिलाई में मजदूरों का कत्लेआम

पहली जुलाई को भिलाई में पांच हजार स्त्री-पुरुष-बच्चों के समूह पर पुलिस ने अन्धाधुन्ध गोलियां बरसाई। रेडियो समाचार के अनुसार गोलीबारी में १६ मौतें हुईं।

जिन पूँजीवादी कानूनों से मजदूरों को कुछ सहूलियत होती है उन्हें आमतौर पर लागू नहीं किया जाता। भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे कानूनों पर अमल करवाने के लिये आनंदोलन को दो साल हो रहे हैं। राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री-मुख्यमन्त्री वडे विपक्षी नेताओं को आवेदन-निवेदन तथा धरने-मूल्हडताल-पीटिंग-जलूसों के सिलसिले के संग साथे की तरह छेंटनी-धारा १४४-कुटकर गुट्ठों व पुलिस रूपी संगठित गुट्ठों के हमले-गिरफ्तारियां चली हैं। सितम्बर ६१ में शकर गुहा नियोगी की हत्या इस घटनाक्रम की एक कड़ी मात्र थी।

नियोगी की हत्या के बाद जहां लीपा-पोती के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने समझौता वार्तायें चलवाई वहीं मैनेजमेंटों के पक्ष में पुलिस का दखल भी बढ़ा दिया। ऐसे में आनंदोलन की अगुआई कर रहे लोगों ने मार्च ६२ में भिलाई ठप्प करने की तैयारी आरम्भ की।

मजदूरों की २६ टोलियाँ भिलाई और इंदू-गिर्द के क्षेत्र में भिलाई ठप्प कार्यक्रम के लिये समर्थन जुटाने में जुट गईं। कार्यक्रम को मिल रहे समर्थन को देख कर राज्य के उद्योग मन्त्री ने हस्तक्षेप किया। भिलाई ठप्प का कार्यक्रम स्थगित किया गया तथा मई में समझौता वार्ताओं का एक और दौर आरम्भ हुआ। १३ जून को इन्दौर में वार्ताओं की असफलता ने पुनः यह स्पष्ट किया कि टाल-मटोल की नीति द्वारा आनंदोलनरत

मजदूरों को बिसरणे के प्रयासों का ही यह वार्तायें भी एक हिस्सा थी।

समझौता वार्ताओं के प्रति आश का था। वार्ता असफलता की स्थिति में तत्काल कदम उठाने के लिये मजदूर एक समूह में एकत्र थे। १३ जून के बाद मजदूरों का यह समूह विभिन्न स्थानों पर डेरे डालते हुये हरकत में आया। एक जुलाई को सुबह ६ बजे पांच हजार मजदूरों का यह समूह अचानक रेल पटरियों पर बैठ गया। भिलाई में मजदूरों ने बम्बई-कलकत्ता रेल मार्ग जाम कर दिया। भारी वरसात के बीच मजदूर रेल पटरियों पर बैठे रहे।

लाठी चांद-अंसू गैस के गोले और फायरिंग में १६ को मार कर तथा बड़ी संख्या में लोगों को धायल करके ही साँच ६ बजे जा कर पुलिस रेल लाइनों से मजदूरों को हटा सकी। क्षेत्र में कफ्यूलगा दिया गया और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है।

भिलाई स्टील प्लान्ट की दली राजहग स्थित लोहा-पत्थर खदानों के मजदूरों के सहयोग से विकसित हुआ, भिलाई-उरला-टेडेसरा-कुम्हारी इन्डस्ट्रीयल परियों की फैक्ट्रीयों के मजदूरों का आनंदोलन जुझारूपन, धीरज और कुर्वानी की शानदार मिसाल है। ऐसे में भिलाई स्टील प्लान्ट के मजदूरों की चुप्पी मजदूर वर्ग पर एक कलंक है।

बढ़ते पैमाने पर मजदूरों की एकता मजदूर पक्ष के निर्माण के लिये आवश्यक है, पूँजीवादी पक्ष से टक्कर लेने के लिये जरूरी है।

हमारे लक्ष्य हैं:— १. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा

पहुँचाने के प्रयास करना। २. पूँजीवाद को दफनाने के लिये जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना। और इसके लिये आवश्यक विश्व के नियोक्ताओं द्वारा एकत्रित करना। ३. भारत में मजदूरों का कान्तिकारी सगठन बनाने के लिये काम करना। ४. फरीदाबाद में

समझौता का आरम्भ करना। ५. सगठन और सघर्ष की राह पर मजदूर आनंदोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिये बेकाम भिले। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के लिये हम प्रयास करेंगे।

डेल्टन के बल्स में तालाबन्दी

३७२ में से २०० मजदूरों की छेंटनी के लिये डेल्टन मैनेजमेंट ने मई माह का वेतन देने से पहले ही एक जून से मध्युरा रोड स्थित प्लान्ट में लाक्षात्तर कर दिया है। तालाबन्दी वाले दिन जलूस और ६ जून को डी सी के पास रेली के अलावा साहबों-मन्त्रियों को आवेदन, लेबर डिपार्टमेंट तक भाग-दौड़ और फैक्ट्री गेट पर ताशों वाला धरना जारी है। डेल्टन मजदूरों को सोचना चाहिये - कैलिवेटर-यामसन प्रेस - के जी खोसला कम्प्रेसर आदि वाले पिटे-पिटाये रास्ते से सफलता के सिलसिला चाल रहती है।

‘मैनेजमेंट किसी की नहीं होती’—इसकी एक और भलक डेल्टन घटनाक्रम में साफ-साफ नजर आती है। दिसम्बर ६० में यूनियन के माँगपत्र पर एक मिनी समझौता हुआ था: मजदूरों की छेंटनी नहीं की जायेगी पर जनरल माँगपत्र पर समझौता नवम्बर ६१ में ही होगा। लेकिन दिसम्बर ६१, जनवरी-फरवरी ६२ में मैनेजमेंट-यूनियन वार्ता में मैनेजमेंट ने समझौते के लिये २०० मजदूरों की छेंटनी की शर्त रखी। समझौता नहीं हुआ।

फैक्ट्री में यूनियन लीडर आमतौर पर काम नहीं करते - मैनेजमेंट ने इसकी छूट देती है। बदले में लीडर लोग मैनेजमेंटों की पालिसियों को मजदूरों के गले उतारने के लिये काम करते हैं। डेल्टन के बल्स में भी कई साल से ऐसा होता है। फिर भी, आधे से अधिक मजदूरों की छेंटनी करवाने में सहयोग देने से यूनियन लीडर आनाकानी करने लगे। इस पर मैनेजमेंट ने “काम नहीं, वेतन नहीं” की आड़ में नेताओं को अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया और ४ नेताओं पर मार-पीट के केस भी बनवा दिये। पलट कर यूनियन लीडरों ने वार किया : डेल्टन के बल्स के

जलानी टूल्स

मई में सैकेन्ट प्लान्ट के रफ ग्राइन्डिंग डिपार्टमेंट की एक शिपिट के प्रत्येक मजदूर को एक हपते हर रोज अंग्रेजी में एक पत्र मैनेजमेंट पकड़ाती रही। मजदूर यह कागज यूनियन लीडरों के पास ले गये। नेताओं ने कहा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ऐसे लंटर देती हो रहती है।

मई की तस्खा जब दी गई तब इन मजदूरों के सौ-डेढ़ सौ रुपये मैनेजमेंट ने काट लिये। तब भाग-दौड़ करने पर इन मजदूरों को पता चला कि मैनेजमेंट ने उन्हें लिख-लिख कर दिया था कि वे प्रोडक्शन कम दे रहे हैं और अधिकारियों के काम करने की कहने पर भी बैठे रहते हैं। जबकि हकीकत यह थी कि उस दौर में डाई बन्टे बिजली नहीं रहती थी और जनरेटर की बिजली रफ ग्राइन्डिंग डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती थी। मजदूरों ने यह बात मैनेजमेंट और यूनियन लीडरों को बताई। देखें-देखें के सिवा मजदूरों को कुछ नहीं मिला। दरअसल सीटू की यूनियन ने गेडोर रफ भलानी टूल्स मैनेजमेंट से एग्रीमेंट की हुई है कि वेतन प्रोडक्शन पर निर्भर होगा और ... और बिजली तथा मैट्रियल की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की नहीं है।

॥ प्लान्ट रफ ग्राइन्डिंग मजदूर जले-भूने थे हो कि जून में एक दिन फिर मैनेजमेंट ने मई बाकी प० २ में

पूँजीवादी चरित्र हिमाचल कर्मचारियों की हड़ताल में साफ-साफ नजर आ रहा है।

दमन-आंतक के बाबजूद जुलाई के आरम्भ में हिमाचल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। राज्य कर्मचारियों की हड़ताल में अन्य मजदूरों का शामिल होना सरकार से टक्कर लेने के लिये आवश्यक है, पूँजीवादी पक्ष के खिलाफ मजदूर पक्ष का निर्माण जरूरी है।

दुनियाँ में मजदूरों के संघर्ष

१. कोरिया

इस वर्ष जनवरी में कोरिया में आठों मजदूरों द्वारा हड़ताल और फैक्ट्री पर कब्जे तथा विरोध में सरकार द्वारा दस हजार हथियारबन्द पुलिस इस्तेमाल करने की घटना के समाचार आमतौर पर अखबारों ने नहीं छापे। यहाँ हम अमरीका के एक छोटे से अखबार न्यूज एन्ड लैंटर्स के मार्च ६२ अक्टूबर में लघी सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं।

दिसम्बर ६१ में उलसान में विशाल हयून्दाई मोटर कम्पनी के मजदूरों ने वेतन वृद्धि, बोनस, वर्किंग कन्डीशनों में सुधार और जेल में बन्द वरकरों की रिहाई की डिमान्डे रखी अपनी माँगों को मनवाने के लिये दबाव डालने के बास्ते मजदूरों ने ओवरटाइम करने से इनकार किया तथा स्लो डाउन आरम्भ किया। जनवरी ६२ में तीस हजार मजदूरों ने हड़ताल के पक्ष में राय जाहिर की हयून्दाई मैनेजमेन्ट ने प्रतिक्रिया में जब तालाबन्दी की कोशिश की तब पाँच हजार मजदूरों ने फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया।

बास्तव में दक्षिण कोरिया सरकार ने हयून्दाई मोटर मैनेजमेन्ट को मजदूरों की वेतन वृद्धि की डिमान्ड ठुकराने को लहा था और मजदूरों का दबाने के लिये लाक-आउट की राह सुझाई थी।

कोरिया सरकार ने फैक्ट्री पर मजदूरों के कब्जे और हड़ताल को तोड़ने के लिये २३ जनवरी को दस हजार हथियारबन्द पुलिस एकत्र दी। मग्नुद गिनारे मिथ्या हयून्दाई मोटर फैक्ट्री को इन दस हजार पुलिसों ने किश्तियों, हैलीकॉप्टरों, अंगूष्ठ गेंस वाले ट्रकों आदि के जरिये धेर कर हमला लोला और संघर्ष कर रहे मजदूरों को फैक्ट्री से खदेड़ा।

तालाबन्दी के खिलाफ फैक्ट्री पर कब्जा करके हयून्दाई मोटर कम्पनी के मजदूरों ने एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। दस हजार हथियारबन्द पुलिस द्वारा हमला बोलकर फैक्ट्री खाली करवाने ने एक फैक्ट्री तक सीमित संघर्ष की सीमायें भी दिखाई हैं खस्ता होती हालत की वजह से सरकारें अब अधिकार्धिक खुलकर मजदूरों पर हमले कर रही हैं — भिलाई हो चाहे उलसान, पेरिस के रेल मजदूर हों चाहे ब्राजील के स्टील वरकर, मामला १८ जैसा है। पूंजीवादी हमलों के खिलाफ मजदूरों के संघर्षों का तीखा होना तो आवश्यक है ही, संघर्षों का फैसला - विस्तृत होना भी-उतना ही ज़रूरी है।

विचौलियों के करम

अल्फा टोयो मजदूरों को चोट

प्रस्तुत हैं १५ मई को अल्फा टोयो मैनेजमेन्ट के साथ डी एल सी की उपस्थिति में फरीदाबाद में एच एस के एक बड़े लीडर द्वारा हस्ताक्षित एग्रीमेन्ट के कुछ अश...

“यूनियन के प्रशिक्षियों ने प्रांग कि उन्हें १९६० १०० नीरीज के अनुपार महंगाई भत्ता (वी डी ए) दिया जाये जो कि ममभौता दिनांक ५-१०-६१ के विपरीत थी। यूनियन के प्रशिक्षियों ने दिनांक ६-४-६२ को डियूटी पर उपस्थित होने के बाद प्रातः ८०० बजे तक गेट मीटिंग की और उसमें कर्मचारियों को दूल डाउन हड़ताल करने को उकसाया। तद्उपरान्त कर्मचारियों ने उस दिन अन्दर आने के बाद दूल डाउन हड़ताल शुरू कर दी जो कि दिनांक ८-४-६२ तक जारी रखी। फैक्ट्री में अनुशासन व्यवस्था की विगड़ती हुई स्थिति और कर्मचारियों द्वारा की गई गेरकानूनी व अनुचित दूल डाउन को जारी रखने की वजह से दिनांक ६-४-६२ को प्रबन्धकों ने तालाबन्दी धोषित की... [वार्ताओं के दौर में समझौता नहीं हो सका किर मी डी एल सी की सलाह पर] प्रबन्धकों ने दिनांक ११-५-६२ को तालाबन्दी का आदेश वापस ले लिया यूनियन के प्रशिक्षियों ने अधिकारियों-मुपरवाइजरों को भी दिनांक ११-५-६२ को अन्दर नहीं जाने दिया। इसप्रकार गतिरोध जारी रहा। अन्ततः... [समझौता] १५-५-६२ को सम्पन्न हुआ।

.... १. कर्मचारीगण तथा यूनियन प्रतिनिधि इस बात से सहमत है कि वे समझौता दिनांक ५-१०-६१ का अधरतः पालन करेंगे और उक्त समझौते के अन्तर्गत जो उत्पादन निर्धारित किया है उसे पूरा-पूरा करके देंगे।”

फिर ढेरों शर्ते पूरी करने की स्थिति में “सदभावना” के तौर पर अल्फा टोयो मैनेजमेन्ट महीने में २५ रुपये मजदूरों को देगी।

विचौलियों के करमों ने ११ सम्पैन्ड वरकर नो बाहर रखे ही हैं, काम कर रहे मजदूरों पर भी इस एग्रीमेन्ट की वजह से मैनेजमेन्ट दन-दना रही है। साइड मीटिंगों में विचार-विमर्श करके ही अल्फा टोयो मजदूर मैनेजमेन्ट-विचौलिया गठजोड़ से निपटने की राह ढूँढ़ पायेंगे।

अमरीका में वर्ग-संघर्ष

रेल हड़ताल-लॉकआउट

यूनियनों को २४ जून से हड़ताल की धमकी देनी पड़ी। हड़ताल की धमकी देने वाली यूनियनों के बीच हजार रेल मजदूर ही सदस्य थे पर मैनेजमेन्ट और अमरीका सरकार भी जानती थी कि हड़ताल शुरू होने पर बाकी दो लाख रेल मजदूर भी उसका समर्थन करेंगे। २४ जून से हड़ताल की धमकी दे रही एक को छोड़कर बाकी यूनियनों ने आखिरी बक्त पर यह स्थिति पंदा हुई। सरकार के दखल से २६ जून को रेल आवागमन शुरू हो गया। अमरीका में वर्ग-संघर्ष की एक झलक के लिये आइये हड़ताल-तालाबन्दी-सरकार के हस्तक्षेप वाले इस घटनाक्रम पर एक नजर दौड़ायें।

अमरीका में माल वाहन में तो रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है ही, हवाई जहाजों और कारों की उल्लेखनीय उपस्थिति के बावजूद रेल यात्रा भी सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है। अमरीका में रेलवे सिस्टम चालीस-बयालीस कम्पनियां संचालित करती हैं। दो लाख बीस हजार वरकर इन कम्पनियों में काम करते हैं। द्रेड के आधार पर संगठित यूनियनों का अमरीका में बोलबाला है पर भारत में यूनियनों से वेक्वालिटी में भिन्न नहीं हैं।

अमरीका में १६६८ से कई रेल वरकरों के वेतन में नाम की भी वृद्धि नहीं हुई है। मैनेजमेन्ट जिस तर्फ एग्रीमेन्ट पर जोर दे रही है उसमें कई मजदूरों की असल तनखा १६ प्रतिशत धट जायेगी - छँटनी, वर्क लोड में वृद्धि और स्वास्थ्य खर्च का दोष अलग से है। इन हालात में रेल मजदूरों और मैनेजमेन्टों के बीच खांचा-तान का बढ़ाना, माहौल का गम्भ होना लाजमी है। यूनियनों और सरकार माहौल को ठन्डा करने का काम करती है पर फिर मीलावा फूट पड़ता है। १६६१ में रेल मजदूरों की हड़ताल पर १८ घन्टों में अमरीकी संसद और राष्ट्रपति ने लाक आउट कर दिया।

बातें कुछ भी क्यों न की जाती हों, अमरीका में भी मजदूरों से निपटने के लिये मैनेजमेन्ट सरकार के शीघ्र और खुलासा हस्तक्षेप की अधिकार्धिक माँग कर रहा है। इसी सिलसिले में सरकार को शीघ्रताशीघ्र कदम उठाने को प्रेरित करने के लिये ही चालीस-बयालीस रेल कम्पनियों की मैनेजमेन्टों ने लाक-आउट वाला कदम उठाया था।

विशाल पैमाने और खर्च कम करने की मजबूरी की वजह से फैक्ट्रीयों के लिये बेरोकटोक ट्रान्सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। कच्चा माल फैक्ट्रीयों तक पहुँचने और तैयार माल फैक्ट्रीयों से उठाने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेल हड़ताल की आशंका भी इसलिये कुछ कदम उठाये भी गये थे। फिर मी, दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता जनरल मोटर्स को ४८ घन्टों रेलवे जाम रहने की वजह से अपनी कई फैक्ट्रीयां बन्द करनी पड़ी थीं।

अपनी व्यवस्था की इस दुखती रग की रेल कम्पनियों की मैनेजमेन्टों को खूब पहचान थी। लाकआउट के

उनके हथियार ने सरकार के तत्काल हस्तक्षेप के रूप में इसीलिये उन्हें फौरन कल दिये।

अमरीका के राष्ट्रपति २४ जून के पहले से ही रेलवे में हड़ताल को राष्ट्रहित के खिलाफ करार दे रहे थे पर संसद में दोनों दाल की सम्भावना थी। लाकआउट करके रेलवे जाम कर मैनेजमेन्टों ने अमरीकी संसद से फौरन कदम उठाये राष्ट्रपति की पहल पर संसद ने फटाफट नया कानून पारित किया। रेल जाम को गैर-कानूनी करार दिया और दो साल से चल रही समझौता वार्ताओं को दो महीने और चलाने को कहा। फिर भी निर्णय नहीं हो पाने पर जबरन पैंच फैसले का प्रावधान उपर से किया। यूनियनों को आड़ चाहिये थी, उन्होंने इस “संसदीय समाधान” को कुछ ना-नुकुर के साथ मान लिया है। भारत हो चाहे अमरीका, पूँजीवादी कानून के दायरे में संघर्षों को सीमित कर दिया जाना मजदूर आन्दोलन के लिये एक गम्भीर समस्या है।

अमरीका में ही ग्रेहाउन्ड रोड ट्रान्सपोर्ट के नो हजार ड्राइवरों की हड़ताल काफी समय से चल रही है। रेल और रोड मजदूरों की ताकत...

— अ.

झलानी टूल्स.....

(१०१ का बाकी)

जैसे ही पत्र मजदूरों को पकड़ा दिया। जून में पत्र मिलते ही मजदूरों ने उसका उत्तर दिया— मैनेजमेन्ट ने मजदूरों के पत्र लेने से इनकार कर दिया.....

मजदूरों द्वारा मैनेजमेन्ट का हल्के से विरोध करने का भी यह असर जरूर हुआ कि मैनेजमेन्ट ने जून में दूसरा-तीसरा-चौथा..... पत्र उन्हें नहीं थमाया।